

मामले में निगम, कर्मचारी गृह कर के निर्धारण हेतु न केवल फ्लैट के कुल मूल्य पर विचार कर रहे हैं अपितु वे स्टैम्प शुल्क को भी आधार बना रहे हैं, यदि हां, तो निर्धारण के प्रयोजनों के लिए यह मूल्य किस नियम के अन्तर्गत जोड़ा जा रहा है; और

(ग) क्या इन कालोनियों के निवासियों ने इस के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योग ब्रह्मबाना): (क) जी हां, श्रीमान् । नगर निगम के अनुसार यह स्वयं अधिकृत सम्पत्तियों के मूल्यांकन का एक तरीका है और दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 के उपबंधों के अनुरूप है ।

(ख) जी हां, श्रीमान् । ऐसी सम्पत्तियों के सम्बन्ध में जिन की पूरी लागत भ्रदा की जा चुकी है और बिक्री दस्तावेज तैयार हो चुका है, मूल्यांकन प्रयोजनों के लिये स्टैम्प शुल्क को भी ध्यान में रखा जाता है । जहां फ्लैट को किशतों के आधार पर खरीदा जाता है वहां पूरी भ्रदायगी होने और बिक्री दस्तावेज तैयार होने के पश्चात् मकान कर निर्धारण के लिये स्टैम्प शुल्क को ध्यान में रखा जाएगा । यह प्रक्रिया दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के उपबंधों के अधीन समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार है ।

(ग) नगर निगम ने सूचित किया है कि अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, उन पर विचार किया गया था और उन्हें रद्द कर दिया गया था ।

Agitations led by Opposition Parties

1207. SHRI SHUSHIL BHATTACHARYA:

SHRI KRISHAN DATT SULTANPURI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the number of agitations led by the Opposition Parties in the States during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): The information furnished by the Governments of Haryana, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Punjab, Sikkim and Union Territory Administrations of Andaman and Nicobar, Arunachal Pradesh, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Lakshadweep, Mizoram and Pondicherry is given in the attached statement.

The information in respect of remaining States/Union Territories is awaited and will be laid on the Table of the House.

Statement

Number of Agitations led by Opposition Parties during last three years (1978, 1979 and 1980)

Name of State/UT	Total No. of agitations
1. Haryana	29
2. Himachal Pradesh	134
3. Manipur	61
4. Meghalaya	nil
5. Nagaland	nil
6. Punjab	7
7. Sikkim	nil
8. Andaman and Nicobar	3
9. Arunachal Pradesh	nil
10. Chandigarh	7
11. Dadra and Nagar Haveli	nil
12. Lakshadweep	nil
13. Mizoram	nil
14. Pondicherry	106